माननीय *एन. के. सोधी और एन. के. सूद से पहले* के समक्ष

**सुल्तान सिंह,-याचिकाकर्ता**

*बनाम*

**हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता**

*1997 का सी. डब्ल्यू. पी. 18294*

7सितंबर, 1999

*भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद* 226-हरियाणा *सहकारी समिति* अधिनियम, *1984-एस. 27 और 114-रोजगार विनिमय* (रिक्तियों *की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959। 2 (च) और 4-सोसायटी के उपनियम-उपनियम 40 (vi)-5 अप्रैल, 1994 को सोसायटी के कुलसचिव-प्रबंध समिति द्वारा याचिकाकर्ता को लिपिक-सह-कैशियर के रूप में नियुक्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करके जारी किए गए निर्देश-प्रत्यर्थी संख्या 5 ने कुलसचिव-अतिरिक्त के समक्ष नियुक्ति को चुनौती दी।पंजीयक* **ने** *याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रबंध समिति याचिकाकर्ता को नियुक्त करने के अपने अधिकार के भीतर थी-राज्य सरकार के प्रतिवादी के समक्ष अपील में यह तर्क देते हुए कि नियुक्ति 1959 के अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन थी, उपनियम 40 (vi) और 5 अप्रैल, 1994 के निर्देशों-राज्य सरकार के सचिव ने प्रतिवादी की अपील को स्वीकार करते हुए 1959 के अधिनियम की धारा 4 (1) 'सोसायटी' को आकर्षित नहीं करती है क्योंकि यह* **न** *तो सरकार के स्वामित्व में है और न ही नियंत्रित है और न ही सरकार द्वारा प्रबंधित है-याचिकाकर्ता की नियुक्ति भी उपनियम 40 (vi) के उल्लंघन में नहीं थी-5 अप्रैल, 1994 के निर्देश सोसायटी पर लागू नहीं होते हैं-राज्य सरकार के आदेशों को रद्द कर दिया गया।*

माना जाता है कि 1959 के अधिनियम की धारा 4 (1) रोजगार कार्यालयों में रिक्तियों की अधिसूचना से संबंधित है।यह आवश्यक है कि एक नियोक्ता सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक प्रतिष्ठान में किसी भी रोजगार में किसी भी रिक्ति को भरने से पहले उस रिक्ति को ऐसे रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित करेगा जो निर्धारित किए जाएं।जहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का संबंध है, रिक्तियों की अधिसूचना की यह आवश्यकता अनिवार्य है।'सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिष्ठान' शब्द को 1959 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (च) में परिभाषित किया गया है, जो यह स्पष्ट करता है कि केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित एक सहकारी समिति सहित एक निगम सार्वजनिक क्षेत्र में एक प्रतिष्ठान होगा बशर्ते वह सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन में हो।वर्तमान मामले में, सोसायटी राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत एक प्राथमिक सहकारी समिति है लेकिन है

न तो सरकार के स्वामित्व में और न ही नियंत्रित और न ही सरकार द्वारा प्रबंधित।यह एक प्राथमिक सोसायटी है जिसकी अपनी प्रबंध समिति है जिसे अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के संदर्भ में चुना जाता है।सोसायटी का प्रबंधन उसकी प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है न कि सरकार द्वारा और इसलिए यह 1959 के अधिनियम की धारा 2 (च) के खंड (3) के अंतर्गत नहीं आता है। यह 1959 के अधिनियम की धारा 2 (च) के किसी भी खंड के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए, यह 'सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिष्ठान' नहीं है।इस प्रकार 1959 के अधिनियम की धारा 4 (1) आकर्षित नहीं होती है।

(पैरा 4 और 5)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि सचिव ने अपील को अनुमति देने और इस आधार पर प्रस्ताव को रद्द करने में कानूनी रूप से गलती की कि रिक्ति को रोजगार विनिमय को अधिसूचित नहीं किया गया था।चूँकि 1959 के अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, इसलिए सोसायटी के लिए किसी भी रोजगार कार्यालय को रिक्ति को अधिसूचित करना आवश्यक नहीं था।

(पैरा 5)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि सोसायटी के उपनियमों के उपनियम 40 में प्रबंध समिति की विभिन्न शक्तियों की गणना की गई है और इसके खंड (vi) में कहा गया है कि प्रबंध समिति समय-समय पर कुलसचिव द्वारा लगाई गई शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए कर्मचारियों की नियुक्तियां कर सकती है।5 अप्रैल, 1994 को जारी किए गए निर्देशों को हरियाणा राज्य के सभी सहकारी शीर्ष संस्थानों, सभी सहकारी चीनी मिलों और सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों को संबोधित किया गया है।ये निर्देश किसी अन्य संस्थान पर लागू नहीं होते हैं।तत्काल मामले में सोसायटी न तो एक सहकारी शीर्ष संस्थान है और न ही एक सहकारी चीनी मिल और न ही एक केंद्रीय सहकारी बैंक है।निर्देश समाज को नियंत्रित करने के लिए नहीं थे।ऐसा होने पर, याचिकाकर्ता की नियुक्ति को उपनियमों के उपनियम 40 (vi) या पंजीयक द्वारा जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

(पैरा 6)

1 .याचिकाकर्ता की ओर *से एस. दलाई, अधिवक्ता।*

अमन दहिया, डी. ए. *जी., हरियाणा, प्रतिवादीगण संख्या 1 और2.*

जयवीर यादव, प्रतिवादी *संख्या 6 के लिए अधिवक्ता*

5 .पी. सिंह, प्रतिवादी *संख्या 7 के* लिए अधिवक्ता।

*निर्णय*

*न्यायमूर्ति एन. के. सोधी,*

(1) 5 द 8 द सरसा कोऑपरेटिव लाईक्रेडिट एंड आईसर्विस 3 सोसाइटी लिमिटेड, आई 8 एस तहसील पेहोवा, जिला कुरुक्षेत्र (संक्षेप में सोसायटी) एक प्राथमिक संस्था है।

हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) के तहत पंजीकृत सहकारी समिति।सरसा गाँव के निवासी पेटिटोनर ने सोसायटी के साथ क्लर्क-

सह-कैशियर के पद के लिए आवेदन किया।यह आवेदन 10 जनवरी, 1996 को आयोजित सोसायटी की प्रबंध समिति की बैठक में रखा गया था और उक्त बैठक में प्रबंध समिति द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा याचिकाकर्ता को इस पद पर नियुक्त किया गया था।प्रत्यर्थी पृथ्वी सिंह ने याचिकाकर्ता को क्लर्क-सह-कैशियर के रूप में नियुक्त करने वाली प्रबंध समिति द्वारा 10 जनवरी, 1996 को पारित प्रस्ताव को रद्द करने के लिए अधिनियम की धारा 27 के तहत पंजीयक के समक्ष एक याचिका दायर की।इस याचिका पर हरियाणा के अतिरिक्त पंजीयक (ऋण) सहकारी समितियों द्वारा सुनवाई की गई, जिन्होंने 30 सितंबर, 1996 के अपने आदेश द्वारा इस धारणा को खारिज कर दिया कि प्रबंध समिति याचिकाकर्ता को नियुक्त करने के अपने अधिकारों के भीतर थी।इस आदेश से व्यथित पृथ्वी सिंह ने अधिनियम की धारा 114 के तहत एक अपील दायर की, जिसकी सुनवाई हरियाणा सरकार के सहकारिता विभाग, चंडीगढ़ के आयुक्त और सचिव ने की।राज्य सरकार के समक्ष यह तर्क दिया गया कि सोसायटी द्वारा की गई याचिकाकर्ता की नियुक्ति रोजगार विनिमय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 (इसके बाद 1959 अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन है क्योंकि रिक्तियों को किसी भी रोजगार विनिमय को अधिसूचित नहीं किया गया था।यह भी तर्क दिया गया कि नियुक्ति उपनियम 40 (vi) और पंजीयक द्वारा 4 अप्रैल, 1994 को जारी किए गए निर्देशों का भी उल्लंघन करती है, जिसमें सहकारी समितियों को केवल अधिशेष पूल से नियुक्तियां करने की आवश्यकता होती है।पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, सचिव ने 12 नवंबर, 1997 के अपने आदेश द्वारा अपील की अनुमति दी और निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

> "उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मैं अपीलार्थी के लिए एल. डी. वकील द्वारा किए गए तर्क से सहमत हूं।30 सितंबर, 1996 का आदेश अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित किया गयाःआर. सी. एस., हरियाणा और 10 जनवरी, 1996 का प्रस्ताव सरसा कॉप की प्रबंध समिति द्वारा पारित किया गया।सी एंड एस सोसायटी को दरकिनार कर दिया जाता है और अपील स्वीकार कर ली जाती है।"

(2) इस आदेश के खिलाफ वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

(3) पक्षों के वकील को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि रिट याचिका सफल होने की हकदार है।

(4) 1959 के अधिनियम की धारा 4 (1) रोजगार कार्यालयों में रिक्तियों की अधिसूचना से संबंधित है।इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान में किसी भी रोजगार में किसी भी रिक्ति को भरने से पहले एक नियोक्ता

सार्वजनिक क्षेत्र में उस रिक्ति को ऐसे रोजगार कार्यालयों के लिए अधिसूचित किया जाएगा जो निर्धारित किए जाएं।जहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का संबंध है, रिक्तियों की अधिसूचना की यह आवश्यकता अनिवार्य है।'सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना' शब्द को 1959 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (च) में परिभाषित किया गया है जो निम्नानुसार हैः

> (च) "सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिष्ठान" से ऐसा प्रतिष्ठान अभिप्रेत है जिसका स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन -
>
> (1) सरकार या सरकार का कोई विभाग।

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित एक सरकारी कंपनी;

(3) केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित एक निगम (एक सहकारी समिति सहित), जिसका स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है;

(4) एक स्थानीय प्राधिकरण;

(5) फिर से?उपरोक्त 3 की परिभाषा के अनुसार केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित एक सहकारी समिति सहित निगम सार्वजनिक क्षेत्र में एक प्रतिष्ठान होगा बशर्ते कि यह सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन में हो।हमारे सामने मामले में, सोसायटी राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत एक प्राथमिक सहकारी समिति है, लेकिन न तो सरकार के स्वामित्व में है और न ही नियंत्रित है और न ही सरकार द्वारा प्रबंधित है।यह एक प्राथमिक सोसायटी है जिसकी अपनी प्रबंध समिति है जिसे अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के संदर्भ में चुना जाता है।सोसायटी का प्रबंधन उसकी प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है न कि सरकार द्वारा और इसलिए यह 1959 के अधिनियम की धारा 2 (च) के खंड (3) के अंतर्गत नहीं आता है। यह 1959 के अधिनियम की धारा 2 (च) के किसी भी खंड के तहत भी शामिल नहीं है। इसलिए, यह 'सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिष्ठान' नहीं है, इसलिए 1959 के अधिनियम की धारा 4 (1) आकर्षित नहीं होती है।हालाँकि, 1959 के अधिनियम की धारा 4 (2) निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों से संबंधित है।इस उप-धारा में यह प्रावधान किया गया है कि उपयुक्त सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि ऐसी तारीख से जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए, निजी क्षेत्र में प्रत्येक प्रतिष्ठान या निजी क्षेत्र में प्रतिष्ठानों के किसी भी वर्ग या श्रेणी से संबंधित प्रत्येक प्रतिष्ठान में नियोक्ता, उस प्रतिष्ठान में किसी भी रिक्ति को भरने से पहले, उस रिक्ति को ऐसे रोजगार अधिशेष के लिए अधिसूचित करेगा जो निर्धारित किया जाए और नियोक्ता उसके बाद ऐसी मांग का पालन करेगा।यह स्पष्ट है कि निजी क्षेत्र में प्रतिष्ठान 1959 के अधिनियम द्वारा शासित होंगे।

केवल तभी जब राज्य सरकार ने उस अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत अधिसूचना जारी की हो। यह प्रतिवादीगण का मामला नहीं है कि ऐसी कोई अधिसूचना हरियाणा राज्य द्वारा 1959 के अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत जारी की गई है। ऐसा होने के कारण, 1959 के अधिनियम के प्रावधान उस समाज पर लागू नहीं होते हैं जो, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, अधिनियम के तहत पंजीकृत एक प्राथमिक समाज है और निजी क्षेत्र में आता है।मामले के इस दृष्टिकोण में, सचिव ने अपील को स्वीकार करने और 10 जनवरी, 1996 के प्रस्ताव को इस आधार पर रद्द करने में कानूनी रूप से गलती की कि रिक्ति को रोजगार कार्यालय को अधिसूचित नहीं किया गया था।चूँकि 1959 के अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, इसलिए सोसायटी के लिए किसी भी रोजगार कार्यालय को रिक्ति को अधिसूचित करना आवश्यक नहीं था।प्रत्यर्थी संख्या 5 के विद्वान वकील ने सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि 1959 के अधिनियम की धारा 4 के प्रावधान अनिवार्य हैं।इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है, लेकिन एकमात्र सवाल यह है कि 1959 के अधिनियम के प्रावधान हमारे सामने समाज पर लागू नहीं होते हैं।प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से उद्धृत मामलों में रिक्तियों को अधिसूचित किया जाना था क्योंकि वे मामले सार्वजनिक क्षेत्र

के प्रतिष्ठानों से संबंधित थे।इसलिए, हम उन निर्णयों को यहाँ विस्तार से संदर्भित करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

(6) तब प्रत्यर्थी संख्या 5-के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति सोसायटी के उपनियमों के उपनियम 40 (vi) का उल्लंघन है और पंजीयक द्वारा 5 अप्रैल, 1994 को जारी किए गए निर्देशों के विपरीत है।मुद्रित उपनियमों और 5 अप्रैल, 1994 के निर्देशों की एक प्रति सुनवाई के समय प्रस्तुत की गई थी।हमने वही देखा है।उपनियमों के उपनियम 40 में प्रबंध समिति की विभिन्न शक्तियों की गणना की गई है और इसके खंड (vi) में कहा गया है कि प्रबंध समिति समय-समय पर कुलसचिव द्वारा लगाई गई शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए कर्मचारियों की नियुक्तियां कर सकती है।5 अप्रैल, 1994 को जारी किए गए निर्देशों को हरियाणा राज्य के सभी सहकारी शीर्ष संस्थानों, सभी सहकारी चीनी मिलों और सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों को संबोधित किया गया है।ये निर्देश किसी अन्य संस्थान पर लागू नहीं होते हैं।तत्काल मामले में सोसायटी न तो एक सहकारी शीर्ष संस्थान है और न ही एक सहकारी चीनी मिल और न ही एक केंद्रीय सहकारी बैंक है।प्रत्यर्थी संख्या 5 के विद्वान वकील द्वारा निर्दिष्ट निर्देश समाज को नियंत्रित करने के लिए नहीं थे।ऐसा होने पर, याचिकाकर्ता की नियुक्ति को उपनियमों के उपनियम 40 (vi) या पंजीयक द्वारा जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

(7) हमारे सामने कोई और मुद्दा नहीं उठाया गया था।

(8) टी के लिए सिद्धांत 3 ने ऊपर कहा, i द।1इम्पग्नड्रॉडर कैन को बनाए रखा जाता है और इसे इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।रिट याचिका की अनुमति लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के दी जाती है।

*आरएनआर*

*अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।*

*दीपांशु सरकार*
*प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी*

*(Trainee Judicial Officer)*

*एन. के. सोधी और एन. के. सूद से पहले, जे. जे.*

द कोट शमीर कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल सोसाइटी लिमिटेड,-याचिकाकर्ता

*बनाम*

पंजाब राज्य और अन्य,-प्रतिवादीगण

*1997 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 18138*

16नवंबर, 1999

*भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद* **226-पंजाब** *सहकारी समितियाँ ए. आई. टी., 1961-एस.* **13,** *55, 56, 63 (बी) और 69-पंजाब सहकारी समिति नियम, 1963-आरएल। 72-गबन* **के** *लिए प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार-अपील खारिज-मांग का लिखित आदेश जारी किया गया।—आयुक्त ने प्रत्यर्थी की अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता-सोसायटी विभाजन के बाद किसी अन्य सोसायटी की राशि की वसूली करने में सक्षम नहीं है-प्रत्यर्थी की संपत्ति की नीलामी-प्रत्यर्थी निर्धारित अवधि के भीतर संपत्ति की बिक्री को चुनौती देने में विफल रहा-उप-पंजीयक नीलामी खरीदार के पक्ष में धारा 72 (14) (iii) के तहत बिक्री की पुष्टि करने वाली पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए-पंजीयक का आदेश उप-पंजीयक के आदेश के खिलाफ धारा 69 के तहत प्रत्यर्थी की पुनरीक्षण याचिका पर विचार करना अधिकार क्षेत्र के बिना है-पंजीयक के साथ-साथ वित्तीय आयुक्त के आदेश भी रद्द कर दिए गए।*

अभिनिर्धारित किया कि बिक्री की पुष्टि करने वाला 8 मई, 1995 का आदेश उप-पंजीयक द्वारा अधिनियम की धारा 63 के तहत पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करके पारित किया गया था। अतः यह माना जाएगा कि उक्त आदेश पंजीयक द्वारा पारित किया गया था और इस प्रकार ऐसे आदेश के विरुद्ध पंजीयक के समक्ष कोई संशोधन दायर नहीं किया जा सकता था।

(पैरा 6)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि उप-पंजीयक ने 8 मई, 1995 को पंजीयक के प्रतिनिधि के रूप में आदेश पारित किया था और इस प्रकार इस आदेश के खिलाफ धारा 69 के तहत पुनरीक्षण याचिका केवल राज्य सरकार के समक्ष हो सकती है न कि स्वयं पंजीयक के समक्ष।इस प्रकार, सहकारी समितियों के पंजीयक का आदेश पारित हो गया